रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2463] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/श्रावण 7, 1941
No. 2463] NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/ SHRAVANA 7, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सं. 12 /2015-2020

विषयः राजस्व वियआसूचना निदेशालय (डीआरआई), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा रेड सैन्डर्स वुड के निर्यात के समय को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 2711(अ)—विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अधिसूचना सं. 6/2015–2020 दिनांक 06–05–2015, अधिसूचना सं. 24/2015–2020 दिनांक 29–08–2016, अधिसूचना सं. 25/2015–2020 दिनांक 02–09–2016, अधिसूचना सं. 40/2015–20 दिनांक 27–11–2017, अधिसूचना सं. 08/2015–20 दिनांक 23–05–2017 और अधिसूचना सं. 48/2015–20 दिनांक 03–01–2019 के साथ पठित अधिसूचना सं. 47 (आर ई–2013)/2009–2014 दिनांक 24–10–2013 में संशोधन करती है।

2. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारें रेड सैंडर्स वुड की शेष मात्रा के निर्यात के लिए यथा लागू विभिन्न इकाईयों को मात्राओं के आंबटन सहित तौर–तरीकों को अंतिम रूप प्रदान करेंगे और निर्यात की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिकतम **31 दिसंबर, 2019** तक पूरा करेंगे।

3. अधिसूचना सं. 24/2015–2020 दिनांक 29–08–2016 (आंध्र प्रदेश अैर डीआरआई हेतु जारी), अधिसूचना सं. 25/2015–2020 दिनांक 02–09–2016 (तमिलनाडु और महाराष्ट्र) और अधिसूचना 40/2015–2020 दिनांक 27–11–2017 (कर्नाटक) के साथ पठित अधिसूचना सं. 47 (आर ई–2013)/2009–2014 दिनांक 24–10–2013 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

सीआईटीईएस द्वारा अनुमत कोटा के अनुसार डीजीएफटी द्वारा प्रत्येक इकाई को आबंटित रेड सैंडर्स वुड की शेष मात्रा के निर्यात के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने और निर्यात की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों को दिनांक 31–12–2019 तक के समय की अनुमति प्रदान की गई है।

[फा.सं. 01/91/180/1380/एएम–12/निर्यात प्रकोष्ठ/खण्ड - III]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक,
विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2019

No. 12 /2015-2020

Subject: Export of Red Sanders wood by Directorate of Revenue Intelligence (DRI), State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka - Extension of time regarding.

S.O. 2711(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act,1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Central Government hereby makes the amendments in Notification No. 47 (RE-2013)/2009-2014 dated 24.10.2013 read with Notification No. 6/2015-2020 dated 06.05.2015, Notification No. 24/2015-2020 dated 29.08.2016, Notification No. 25/2015-2020 dated 02.09.2016, Notification No. 40/2015-20 dated 27.11.2017, Notification No. 08/2015-20 dated 23.05.2017 and Notification No. 48/2015-20 dated 03.01.2019

2. Directorate of Revenue Intelligence (DRI) and State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka shall finalize the modalities including allocation of quantities to various entities, as applicable, for export of the balance quantity of Red Sanders wood and shall complete the whole process of export latest by **31st December, 2019.**

3. Other provisions of Notification No. 47 (RE-2013)/2009-2014 dated 24.10.2013 read with Notification No. 24/2015-2020 dated 29.08.2016 (for Andhra Pradesh and DRI), Notification No. 25/2015-2020 dated 02.09.2016 (for Tamil Nadu and Maharashtra) and Notification No. 40/2015-20 dated 27.11.2017 (for Karnataka) shall remain unchanged.

4. **Effect of this notification:**

Time upto 31.12.2019 has been allowed to the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) and State Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka to finalize the modalities and complete the entire process of export of balance quantity of Red Sanders wood allocated to each entity by the DGFT against the quota permitted by CITES.

[F.No. 01/91/180/1380/AM-12/EC/Vol. III]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.30 22:49:40 +05'30'